अफगानिस्तान की ओर : 2+2 वार्ता पर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

05 सितम्बर, 2018

द हिन्दू

लेखक :
सुहासिनी हैदर (संपादक)

''2+2 वार्ता को अमेरिकी नीति के साथ-साथ इस क्षेत्र में भारत की भूमिका पर भी ध्यान देना चाहिए।''

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अफगानिस्तान के लिए अपनी दक्षिण एशिया नीति की घोषणा के एक साल बाद, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इस हफ्ते फिर से इस क्षेत्र में दिखाई देंगे। राज्य सचिव माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव जेम्स मैटिस गुरुवार को अपने भारतीय समकक्ष, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पहली 2+2 वार्ता करेंगे। जहाँ एक तरफ श्री मैटिस का काबुल से आने की उम्मीद है, तो वहीं श्री पोम्पियो और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के जनरल चेयरमैन जनरल जोसेफ डनफोर्ड का इस्लामाबाद से आने की उम्मीद है।

एक साल बाद

आज अफगानिस्तान उस स्थिति में नहीं है कि वो याद करे कि कैसे श्री ट्रम्प ने पिछले अगस्त में इसके बेहतर के लिए सोचा था चाहे वो सुरक्षा की स्थिति का ममला हो, शांति प्रक्रिया के साथ-साथ आर्थिक विकास के क्षेत्रीय समाधान का मामला हो। पिछले कुछ हफ्तों में हिंसा में तेजी देखी गई है, तालिबान ने अफगानिस्तान के आसपास समेकित हमलों का एक सेट तैयार कर रखा है, राष्ट्रपति अशरफ गनी द्वारा तीन महीने के युद्धविराम की पेशकश को खारिज कर दिया और गजनी शहर में घेराबंदी की है। अमेरिकी विशेष बल और अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल उन्हें साफ करने में सक्षम थे।

अगस्त में गजनी और अन्य शहरों में तालिबान के हमले का असर, जिसमें काबुल के स्कूल में घातक बमबारी भी शामिल थी, तीन स्तरीय था। भावनात्मक सार्वजनिक वक्तव्य में, श्री गनी ने अफगान-पाकिस्तान सीमा के निकट अस्पतालों में आतंकवादियों के इलाज के आरोप में पाकिस्तान पर आरोप लगाया, जबकि रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लश्कर-ए-तोइबा सहित पाकिस्तानी सेनानियों विद्रोहियों में से थे। पाकिस्तान ने आरोपों से इंकार कर दिया, यह सुझाव दिया कि मृत पाकिस्तानी वास्तव में गजनी में काम कर रहे मजदूर थे। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल हुए हिंसा ने अफगान नागरिकों के लिए सबसे घातक वर्ष है, जिसमें हर दिन नौ लोगों की मौत हो जाती है।

काबुल की सुरक्षा संरचना ने बाद में बेकार और इस्तीफे की नाटकीय श्रृंखला देखी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हनीफ अमार का स्थान यू.एस. में अफगानिस्तान के राजदूत हम्दुल्ला मोहिब से बदल दिया गया। सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख सभी ने श्रीमान गनी के कामकाज के साथ मतभेद होने पर अपने इस्तीफे दे दिए; हांलाकि, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। बढ़ती शांति प्रक्रिया के साथ-साथ विकास अक्टूबर में होने वाले संसदीय चुनावों के साथ-साथ अप्रैल, 2019 में राष्ट्रपति चुनावों को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाएगा।

ईरान दृष्टिकोण

ईरान के साथ ट्रम्प प्रशासन की लड़ाई दक्षिण एशिया नीति को समझने में एक और बाधा है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक पड़ोसी है और तेहरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। ईरान समुद्र तट पर अफगानिस्तान के व्यापार मार्गों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी है, जो चाबहार बंदरगाह के विकास से पाकिस्तान को रोकने की भारत की इच्छा से जुड़ा हुआ है। वास्तव में, अगर वाशिंगटन को तेहरान के साथ मतभेद नहीं होता, तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को वैकल्पिक आपूर्ति लाइनों तक पहुंच से फायदा हो सकता है।

इसके बाद, भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव तरीके से अफगानिस्तान की सहायता करने पर ध्यान देना चाहिए कि देश का चुनाव जितना संभव हो सके शांतिपूर्ण हो। भारत की विकास सहायता अफगान नागरिकों के बीच काफी प्रभावी और सद्भावना का स्रोत रही है और भारत द्वारा इसमें कमी करने का समय नहीं है। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2015-2016 में 880.44 करोड़ के वायदे की तुलना में 2017-18 में व्यय 365.96 करोड़ ही थी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि 2008-09 में शुरू हुई काबुल में सल्मा बांध और संसद भवन जैसी प्रमुख परियोजनाएं अब पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को दुबारा क्यों नहीं बनाया जा रहा है? वर्ष 2016 में शुरू हुई लघु विकास परियोजनाओं की वर्तमान फसल, काबुल सहित कई शहरों के लिए पेयजल योजनाएं, बसों की आपूर्ति, कम लागत वाले आवास का निर्माण और स्वास्थ्य और शिक्षा में सहायता महत्वपूर्ण है।

दुगुनी तेजी दिखने की आवश्यकता

सैन्य मोर्चे पर भी, भारत को अफगान हार्डवेयर के लिए हेलीकॉप्टरों के साथ-साथ इंजीनियरिंग/तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द हाथ बढ़ाना चाहिए। चाबहार में भारत की योजनाएं अन्य विचारों से स्वतंत्र अफगानिस्तान में अपनी सीमा को कायम रखने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, और अगले सप्ताह त्रिपक्षीय भारत-अफगानिस्तान-ईरान बैठक के लिए विदेश सचिव विजय गोखले की काबुल की यात्रा उन्हें आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी।

आखिरकार, सरकार को यह महसूस करना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ समस्याओं की वजह से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की निरंतर उत्साह में कमी ने उपमहाद्वीप के साथ अफगानिस्तान की भागीदारी को भी कमजोर कर दिया है, जिसे भारत ने बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत की थी। गुरुवार को 2+2 की बैठक में भारत को न सिर्फ श्री ट्रम्प की दक्षिण एशिया नीति में भागीदारी पर ध्यान देना होगा, बल्कि इसे अपने पड़ोस में अपनी भूमिका पर भी ध्यान देना होगा।

GS World टीम...

2+2 डायलॉग चर्चा में क्यों?

- लगातार टलती आ रही भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग या बातचीत 6 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाली है।
- पिछले कुछ सालों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच गहराते संबंधों को यह बातचीत एक और अहम मोड़ दे सकती है।
- बातचीत में भारत की ओर से रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हिस्सा लेंगी, जबकि अमेरिका की ओर से रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो यह पहल करेंगे।

2+2 डायलॉग क्या है?

- यदि दो देशों के बीच एक साथ ही दो-दो मंत्रिस्तरीय वार्ताएँ आयोजित की जाएँ तो इसे 2+2 संवाद मॉडल का नाम दिया जाता है।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद मॉडल में दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के सचिवों के बीच वार्ता हो रही है।
- विदित हो कि इस संवाद मॉडल के तहत भारत और जापान की भी वार्ता हुई है।

दोनों देशों के बीच व्यापार

- भारत से अमेरिका को हर साल लगभग 1.5 अरब डॉलर के स्टील और एल्युमिनियम उत्पादों का निर्यात किया जाता है।
- वर्ष 2016-17 में भारत से अमेरिका को किया जाने वाला कुल निर्यात 42.21 अरब डॉलर, जबकि कुल आयात 22.3 अरब डॉलर का था।

भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दरार का कारण

- भारत ने ईरान से सभी तेल आपूर्ति पर कटौती करने से इंकार कर दिया है, जिससे अमेरिका नाराज है।
- भारत द्वारा रूसी एस-400 मिसाइल प्रणाली की खरीद की योजना पर।
- भारत द्वारा यू.एस. से आयातित कई वस्तुओं पर उच्च शुल्क लगाना।
- विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में कई मुद्दे/विवाद; व्यापार संरक्षणवाद; नए अमेरिकी स्टील और एल्यूमीनियम टैरिफ पर विवाद; चिकित्सा उपकरणों पर भारतीय मूल्य में कटौती पर विवाद।

काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए)

- इसे जनवरी, 2018 में लागू किया गया था। यह ट्रम्प प्रशासन को रूस के रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन में शामिल संस्थाओं को दंडित करने का अधिकार देता है।

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत की सहायता से विकसित किया जा रहा चाबहार बंदरगाह ईरान तट पर स्थित है।
2. सलमा बांध, अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित में से किस देश की सीमाएं ईरान से लगी हुई है?

(a) अफगानिस्तान और पाकिस्तान
(b) भारत और अफगानिस्तान
(c) पाकिस्तान और भारत
(d) सीरिया और ईराक

1. Consider the following statements

1. Chabahar port, which is developed by the assistance of India is situated on the coast of Iran.
2. Shalma Dam is situated at Kabul, Afghanistan.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

2. Which of the following Countries borders with Iran.

(a) Afghanistan and Pakistan
(b) India and Afghanistan
(c) Pakistan and India
(d) Syria and Iraq

नोट :

04 सितम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a), 2(c) होगा।

GS World
Dedicated To Excellence

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. हाल ही में होने वाली भारत-अमेरिका के मध्य 2+2 संवाद काफी चर्चा में है। इस संवाद में भारत को अमेरिका के दक्षिण एशिया नीति में अपनी भागीदारी पर तो ध्यान देना ही होगा, साथ ही अपने पड़ोसियों के संबंध में अपनी स्पष्ट भूमिका भी दर्शानी होगी। चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

2+2 dailogue between India and America which is going to be held soon is in much debate. In the dialogue India has to focus on her role in the America's South East Policy along with clearly showing in relationship with her neighbours. Comment.

(250 Words)